

संपादकीय : कसौटी पर सूची

इसमें कोई दोराय नहीं कि देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए होने वाले चुनाव में सभी वैध मतदाताओं को मतदान का अधिकार होना चाहिए और नियम के मुताबिक अपात्र लोगों को मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश के मायने समझे जा सकते हैं। सवाल है कि अगर इस सूची को दुरुस्त करने के क्रम में किसी मजबूरी या अन्य परिस्थितियों की वजह से वैसे लोग भी मतदान के अधिकार से वंचित हो जाते हैं, जो वास्तव में इसके हकदार हैं, तो इसकी जवाबदेही किस पर होगी। यह सही है कि समय-समय पर अलग-अलग वजहों से अपात्र हो चुके लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की जरूरत होती है। लेकिन अब नई परिस्थितियों में जिस तरह चुनाव आयोग ने सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत की है, उसमें इस बात की आशंका खड़ी हो गई है कि क्या इसमें बड़ी तादाद में वैसे लोग भी मतदान के लिए अपात्र करार दिए जाएंगे, जिनके पास आयोग की ओर से मांगे गए दस्तावेज किन्हीं वजहों से उपलब्ध नहीं हैं ! मतदाता सूची को त्रुटियों से रहित बनाने का काम निश्चित तौर पर संवैधानिक रूप से सही है, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से इसके औचित्य पर सवाल उठाने के भी अपने आधार हैं, आयोग की ओर से इस सूची में बने रहने के लिए जिन स्वीकार्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, बिहार के बहुत सारे लोगों को लिए यह एक बेहद मुश्किल काम होगा। ऐसे लोगों की भी संख्या अच्छी-खासी होगी, जिनके पास खुद को सही साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे और अगर वे इन्हें नए सिरे से बनवाने के काम में लगेंगे तो इसके लिए समय की जरूरत होगी। जबकि बिहार में अक्टूबर में ही विधानसभा

चुनाव होने हैं और मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए महज एक माह का समय दिया गया है। स्वाभाविक ही इस समय के चुनाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, अगर उसमें शामिल होने के पात्र लोग किन्हीं वजहों से छूट गए, तो उनके दावों और आपत्तियों को निपटाने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी ? यह छिपा नहीं है कि बिहार में एक बड़ी आबादी ऐसे गरीब और कम शिक्षित लोगों की है, जिनके पास सरकार की ओर से जारी आधिकारिक दस्तावेज नहीं होंगे। खासतौर पर जन्म पंजीकरण के मामले में काफी पीछे रहने की वजह से बहुत कम लोगों के पास जन्म प्रमाणपत्र हैं। हालांकि हाशिये के समुदायों के ज्यादातर लोगों की पहुंच आधार और राशन कार्ड तक है, जिनकी मांग आमतौर पर हर चीज के लिए की जाती है। मगर यह समझना मुश्किल है कि आखिर किन वजहों से इन्हें स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से भले ही यह कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को ताजा दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग इस दायरे में आएंगे, उनके लिए भी निर्धारित दस्तावेज जमा करना आसान नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों के मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका जताई जा रही हैं। और विपक्षी दल इस कवायद को समान अवसर के खिलाफ बता रहे हैं। ऐसे में आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि नए नियमों की वजह से किसी भी वैध मतदाता के मतदान का अधिकार का हनन न हो।

महंगा सफर

शहरों - महानगरों में सार्वजनिक परिवहन की सीमाओं की वजह से आम आदमी आवश्यकता पड़ने पर पेप आधारित कंपनियों के वाहनों से अपने गंतव्य तक आवाजाही कर लेता था। मगर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नए दिशा-निर्देश लागू होने के बाद ऐसे वाहनों से सफर महंगा होने की स्थिति में अब लोगों को सोचना पड़ेगा। अव्वल तो व्यस्त समय को कारण बना कर समान दूरी तक सफर के लिए दोगुना किराया लेना अनुचित है, फिर यह बेहद निराशाजनक है कि पहले ही महंगाई के बोझ से दबे आम लोगों पर किराए की मार के साथ-साथ बुकिंग रद्द कर देने पर जुर्माना लगाने का नियम भी सख्त कर दिया गया है। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं इससे यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा पाया गया है कि कैब कंपनियों की गाड़ियां समय पर नहीं आतीं। ऐसे में लोगों को विवश होकर अपनी बुकिंग रद्द करनी पड़ती है। वहीं चालकों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है। वे कई बार यात्रा का डिजिटल भुगतान करने पर जोर देते हैं और पसंद का गंतव्य न मिलने पर खुद भी बुकिंग रद्द

कर देते हैं। हालांकि अब ऐसे चालकों की नकेल कसने के लिए उन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि राज्य सरकारों को नए दिशा-निर्देश लागू करने की सलाह के बाद आम लोगों पर ही इसका आर्थिक बोझ बढ़ेगा। व्यस्त समय में किराया बढ़ाने का चलन नया नहीं है। मगर मूल्य निर्धारण का यह मनमाना तरीका आखिरकार यात्रियों की जेब पर भारी पड़ता है। कैब सेवा प्रदाता कंपनियों को दोगुना किराया लेने की अनुमति देने से पहले यात्रियों की शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने की जरूरत थी। हाल में आए एक सर्वेक्षण में आधे से अधिक यात्रियों का कहना है कि इन कंपनियों की सेवाएं बेहतर नहीं हैं। कई बार तो गाड़ियों के लिए देर तक इंतजार करना पड़ता है। वाहनों की साफ-सफाई और चालकों के खराब व्यवहार पर भी लोग प्रायः सवाल उठाते रहे हैं। अचानक किराया बढ़ा दिए जाने से लोग पहले ही परेशान थे। अब तो सीधे-सीधे लोगों की जेब से दोगुना किराया वसूलने की व्यवस्था थोप दी गई है। नए दिशा-निर्देश से आखिरकार आम लोगों को ही नुकसान होगा।

उदयपुर वन विभाग की आरटीआई पर ‘सीनाजोरी’, भ्रष्टाचार पर जवाब देने के बजाय आवेदक को ठहराया दोषी! प्रभावशाली लोगों के आगे क्यों हो गए नतमस्तक??



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। क्या उदयपुर का वन विभाग और उसके अफसर अब केवल नेताओं और प्रभावशाली लोगों का ही काम करते हैं? क्या वे सिर्फ उन्हीं के हितों की रक्षा के लिए जनता के सूचना के अधिकार की बलि देने को हरदम तैयार रहते हैं? क्या सार्वजनिक संसाधनों पर खुद को चौकीदार समझने वाले ये अफसर अब चौधरी बन बैठे हैं, जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के इशारे पर गोपनीयता की चादर ओढ़ लेते हैं? यदि जमीन पर कुछ गलत हो चुका है और उसे उजागर करने के लिए कोई नागरिक आरटीआई लगाता है तो क्या उसे गुनहगर समझा जाएगा? यह सवाल इसलिए अहम हो गया है क्योंकि वन विभाग की जमीन की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की है, वे खुद जनता के सवालों से मुंह चुराते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक आरटीआई के जवाब में वन विभाग की ओर से जिस प्रकार की बेरुखी और सीनाजोरी वाला रवैया सामने आया, वह न केवल हैरान करने वाला है बल्कि चिंताजनक भी है। विभाग की जमीन पर होटल बन चुका है, मगर जब यह पूछा गया कि क्या विभाग ने कोई अनुमति दी है तो जवाब देने की बजाय आवेदक को ही दोषी ठहरा दिया गया। विभाग के अफसर इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे सूचना मांगकर कोई बड़ा अपराध कर लिया गया हो।

सीसारमा की जमीन पर होटल, गूगल मैप दिखा रहा होटल तो विभाग कह रहा, सवाल मत पूछो

मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में देश के प्रख्यात आरटीआई



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। उदयपुर एयरपोर्ट से कांग्रेस का राजनीतिक हमला तेज हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भजनलाल शर्मा की सरकार पूरे पांच साल चलेगी, लेकिन इस दौरान आम जनता को भारी कष्ट उठाने पड़ेंगे क्योंकि इस सरकार के पास न कोई स्पष्ट नीति है, न निर्णय लेने की क्षमता और न ही जनहितकारी योजनाओं की समझ। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का पूरा ध्यान केवल भ्रम फैलाने, बेमतलब के भाषण देने और जनता को गुमराह करने पर केंद्रित है। डोटासरा उदयपुर संभाग के कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए मोडिया से बातचीत की। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इस अवसर पर उनके साथ थे। डोटासरा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों को जनविरोधी बताते हुए कहा कि जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही और प्रशासनिक व्यवस्था ठप है। उन्होंने तंज कसा कि डबल इंजन सरकार में से

एक्टिविस्ट और पत्रकार जयवंत भैरविया ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अलग-अलग आवेदन किए गए, जिनमें से तीन पर विभाग की ओर से ‘आदेश’ पारित किए गए। इन आवेदनों में विभागीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और अधिकारियों द्वारा पद के दुरुपयोग से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थीं।

एक आरटीआई में सीसारमा क्षेत्र की उस जमीन पर सवाल किया गया जो विभागीय रिकॉर्ड में वन विभाग की दिख रही है लेकिन गूगल मैप पर उसी स्थान पर एक बड़ा होटल बना हुआ है। आरोप है कि यह होटल 340 कमरों वाला सेवन स्टार होटल है, जो स्पष्ट रूप से वन विभाग की भूमि पर बना हुआ प्रतीत होता है। आवेदक ने यह जानकारी मांगी कि क्या इस होटल को निर्माण, एनओसी या पर्यावरणीय स्वीकृति विभाग ने दी है? इसके जवाब में विभाग ने सूचना देने की बजाय आवेदक की मंशा पर सवाल उठा दिए।

सुनवाई 23 दिसंबर की, आदेश 23 जून का तो अपलोड किया जुलाई में!

इस आवेदन की प्रथम अपील की सुनवाई 23 दिसंबर 2024 को तय की गई, लेकिन इसका आदेश 7 महीने बाद 23 जून 2025 को पारित किया गया और जुलाई में ऑनलाइन अपलोड किया गया। इतना ही नहीं, आदेश में लिखा गया कि “अपीलार्थी सूचना प्राप्त हेतु गंभीर नहीं है और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, अतः अपील निरस्त की जाती है।” यह आदेश खुद सीसीएफ सुनील चिंद्री द्वारा पारित किया गया। जरा तारीखों पर गौर कीजिए। कब आवेदन किया गया, कब आदेश पारित किया गया? आवेदक का कहना है कि उन्हें सुनवाई संबंधी कोई सूचना नहीं मिली। यह आजकल आरटीआई से मना करने का आजमाया हुआ पैतरा होता जा रहा है। इसके बाद भी यदि उस दिन सुनवाई हुई तो दो लाइन का आदेश देने में इतना समय कैसे लग गया??? इतने व्यस्त और इतने वीआईपी तो सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग भी नहीं हैं। आदेश की यह लेटलतपी कहीं आफ्टर थॉट तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इनको भी आदेश डिस्टेट तो नहीं करवाया??? हद है, खुद के खिलाफ आरटीआई की सुनवाई खुद कर रहे अफसर सबसे हैरानी की बात यह रही कि जिनके खिलाफ सूचना मांगी गई सीसीएफ सुनील चिंद्री, वही अधिकारी अपील की सुनवाई भी खुद कर रहे हैं। यह सीधे-सीधे “प्राकृतिक न्याय” के सिद्धांतों का मजाक है। यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी को इतना भी बोध नहीं कि जिस पर आरोप है स्वयं अपने ही मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, तो यह उसके ज्ञान और नैतिकता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है। यदि अफसर खुद सुनवाई करेगा तो नियमों का मजाक बनाना तय है। दूसरी आरटीआई में मांगी गई निजी और सरकारी वाहनों की जानकारी, मिला वही ‘कॉपी-पेस्ट’ जवाब दूसरे आवेदन में यह जानकारी मांगी गई कि सीसीएफ सुनील चिंद्री किस वाहन का उपयोग कर रहे हैं, क्या उस पर लाल

नीली बत्ती लगी है, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? साथ ही पूछा गया कि उनके बंगले पर घरेलू कार्यों के लिए वन विभाग के किन-किन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है और उन्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? इसके अतिरिक्त यह भी पूछा गया कि उनका गृह जिला क्या है, वे उदयपुर में कितने वर्षों से पदस्थ हैं और क्या उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों को निजी कुत्ते की देखभाल के लिए अधिकृत किया है? इन सभी प्रश्नों का जवाब वही पुराना कॉपी-पेस्ट जवाब था - “आवेदक गंभीर नहीं प्रतीत होता।” तीसरे आवेदन में मांगी गई ‘लाल बत्ती वालों’ की सूची, मगर जवाब फिर वही - आवेदक ही दोषी! तीसरे आवेदन में वन विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम व पदनाम मांगे गए, जिनके निजी या सरकारी वाहनों पर लाल पट्टी, “राजस्थान सरकार” लिखा हुआ हो या फिर लाल नीली बत्ती लगी हो। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर की भी जानकारी मांगी गई थी। इस आवेदन को भी उसी तरह ‘असंजीदगी’ का नाम देकर खारिज कर दिया गया। एक ही जवाब तीनों आवेदनों में कॉपी पेस्ट की कला का मुजाहिरा करते हुए एक सा जवाब चिपका दिया गया।

कानून की अवहेलना: तय 45 दिन में सुनवाई नहीं, आदेश देने में लगे सात महीने

सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम अपील की सुनवाई 45 दिन में अनिवार्य है, लेकिन यहां आदेश देने में सात महीने लगा दिए गए और जवाब में तथ्यों की बजाय तंज परोसे गए। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब विभाग खुद पारदर्शिता से डरने लगे तो कैसे उस पर भरोसा किया जा सकता है?

करणी माता रोपवे व अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों पर भी नहीं दे रहा जवाब

उदयपुर में करणी माता रोपवे के संचालन व परमिशन से जुड़ी आरटीआई पर भी विभाग जानकारी नहीं दे रहा। जबकि यदि यह वन भूमि या इको सेंसिटिव जोन में आता है तो यह सीधे-सीधे नियमों का उल्लंघन है।

सूचना मांगना गुनाह, जवाब देना ‘मेहरबानी’? सवाल स्पष्ट हैं कि जब वन विभाग की सरकारी जमीन पर वाणिज्यिक निर्माण हो रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है, तब उसका जवाब देने से विभाग क्यों कतरा रहा है? क्या अफसरों का कोई आर्थिक हित है, राजनीतिक आकाओं से वे दबे जा रहे हैं या फिर कोई और वजह है? आरटीआई जैसी संवैधानिक प्रक्रिया को यदि इसी तरह मजाक बना दिया जाएगा तो पारदर्शिता की उम्मीदें भी दम तोड़ देंगी। क्या हमारे जनप्रतिनिधि इस पर संज्ञान लेंगे? क्या राज्य सरकार इस ‘भांग मिले सिस्टम’ की जांच कराएगी? अब समय है कि जनहित में उठ रही आवाजों को दबाने की बजाय उन्हें सुना जाए क्योंकि ये सवाल जनता के हैं, और जवाब भी जनता को ही मिलना चाहिए।

7 जुलाई को जयपुर-उदयपुर सिटी रेलसेवा रहेगी रेगूलेट



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर/जयपुर, 4 जुलाई। रेलवे प्रशासन द्वारा अजमेर मंडल के अन्तर्गत आने वाले अजमेर-चन्देरिया रेलखण्ड पर स्थित नसीराबाद यार्ड में समपार फाटक संख्या 18 पर आवश्यक तकनीकी कार्य किया जाएगा। इस कार्य हेतु 7 जुलाई, 2025 को एक नियोजित ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके कारण इस खंड से गुजरने वाली कुछ रेलसेवाओं के संचालन

में आंशिक परिवर्तन किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार, इस ब्लॉक के प्रभावस्वरूप जयपुर से उदयपुर सिटी के लिए चलने वाली गाड़ी संख्या 12992 को 7 जुलाई को अजमेर स्टेशन पर एक घंटे तक रोका जाएगा। यह अस्थायी

रेगुलेशन रेलवे की ओर से सुगम व सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने हेतु किया जा रहा है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पूर्व संबंधित ट्रेन की समय-सारणी की जानकारी अनिवार्य रूप से प्राप्त करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु संबंधित स्टेशनों व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सूचना प्रदर्शित की जा रही है।

पर्यटकों के लिए शनिवार को बंद रहेगा सज्जनगढ वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जैविक उद्यान

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 04 जुलाई। सज्जनगढ वन्यजीव अभ्यारण्य एवं सज्जनगढ जैविक उद्यान 5 जुलाई शनिवार को पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। उप वन संरक्षक वन्यजीव यादवेंद्रसिंह

चूण्डावत ने बताया कि सज्जनगढ महल परिसर में बने धार्मिक स्थल पर शनिवार को श्रद्धालुओं के पैदल जाने के लिए सज्जनगढ जैविक उद्यान एवं सज्जनगढ वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए बंद रहेगा।

उदयपुर सर्राफा बाजार : तीन दिन में चांदी में 450 की गिरावट, सोने में 250 तक नरमी



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। उदयपुर सर्राफा बाजार में बीते तीन दिनों के दौरान सोने और चांदी के दामों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला। चांदी में 450 प्रति किलो की गिरावट आई, वहीं सोना स्टैंडर्ड (999) में 250 प्रति 10 ग्राम की नरमी दर्ज की गई। सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार 2 जुलाई 2025 को चांदी

टंच का भाव 1,07,300 प्रति किलो था, जो 3 जुलाई को घटकर 1,06,800 और 4 जुलाई को 1,06,850 रह गया। इसी तरह चांदी चौरसा का भाव 2 जुलाई को 1,06,500,

3 जुलाई को 1,06,000 और 4 जुलाई को 1,06,050 प्रति किलो दर्ज किया गया। इस तरह तीन दिन में चांदी टंच और चौरसा — दोनों में 450 प्रति किलो की गिरावट रही। इसी प्रकार सोने की बात करें तो सोना स्टैंडर्ड (999) का भाव 2 जुलाई को 98,600, 3 जुलाई को 98,300 और 4 जुलाई को 98,350 प्रति 10 ग्राम रहा। कुल मिलाकर इसमें 250 की गिरावट दर्ज की गई। सोना जेवराती (23 कैरेट) 2 जुलाई को 94,655, 3 जुलाई को 94,370 और 4 जुलाई को 94,415 प्रति 10 ग्राम रहा। इसमें 240 की कमी आई। वहीं सोना (22 कैरेट) का भाव 2 जुलाई को 90,710, 3 जुलाई को 90,435 और 4 जुलाई को 90,480 प्रति 10 ग्राम रहा, जिससे इसमें तीन दिन में 230 की गिरावट रही। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण घरेलू सोना-चांदी की कीमतों में भी असर देखने को मिला। हालांकि शुक्रवार को बाजार में हल्की रिकवरी नजर आई।



खबर का जबर्दस्त असर : आयड़ में गुमनाम पौधों को मिला बांस की बैसाखी का सहारा, तालाबंदी के बावजूद गम गलत करने वालों का सिलसिला जारी



24 न्यूज अपडेट

ट्रवटी फोर न्यूज अपडेट की खबर का जबर्दस्त असर हुआ है। कल हमने खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से नेताओं और अफसरों के लगाए हुए पौधों को बांस की खपची का सपोर्ट देकर खड़ा कर दिया गया था जबकि बाकी सभी पौधों को बिना सपोर्ट के मरने को छोड़ दिया गया था। आयड़ में पौधारोपण के इस सच के सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। अफसरों व नेताओं ने अपनी ईसल्ट को फील करते हुए आज अचानक आनन-फानन में सिस्टम के सहारे को तरस रहे पौधों को बांस की बैसाखियां उपलब्ध करवा दी। पौधों के तनों से बांस बांधकर उन्हें सीधा खड़ा कर दिया गया। हम इसे जनता के हौसले और हमारे दर्शकों व पाठकों की आवाज की जीत कहेंगे। आपको बता दें कि कई बार अपने पद और एप्रोच के गुरूर में डूबकर हमारे नेता, जनप्रतिनिधि और अधिकारी यह भूल जाती है कि उनकी अंतिम जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता ना तो उनकी गुलाम है ना ही नौकर। ना वो यह दर्जा रखती है कि उसके साथ ऐसा बतांव किया जाए मानों कोई अहसान किया जा रहा है। आज अचानक बांस की बैसाखियों का प्रकट होना बता रहा है कि यह काम एक दिन पहले भी किया जा सकता था। लेकिन इच्छाशक्ति का अभाव था। सब कुछ मैनेज करने वालों को शायद लगा कि केवल वीआईपी को मैनेज करने से काम चल जाएगा, जनता तो क्या ही बोलने वाली है। लेकिन ऐसे लोग कान खोलकर सुन लें कि

ऐसे मुद्दों पर ट्रवटी फोर न्यूज अपडेट की टीम हमेशा मुखर रहने वाली है। आयड़ में पौधे लगाने का काम लगातार जारी है लेकिन अब तक अन्य किसी भी पौधे पर नाम की तख्तियां नहीं लगी हैं। इस बारे में सवाल आज भी वहीं का वहीं है कि आखिर तख्तियां लगाने का काम कौनसी सरकारी एजेंसी कर रही है। पैसा कहां व किस काउंटर पर जमा हो रहा है। इसकी सूचना कब जारी की गई? यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी अन्य एजेंसी पैसा जमा कर रही तो किस अधिकार के तहत ऐसा हो रहा है। बहरहाल, आज जब हमारी टीम पौधों का हाल चाल जानने के लिए आयड़ पहुंची तो देखा कि कल जो प्रवेश द्वार खुला था, आज उस पर ताला लगा दिया गया है। संभवतः आयड़ के विकास के 85 करोड़ से ज्यादा के काम को और नए लगाए पौधों को पशुओं से बचाने की मंशा रही होगी। लेकिन जब हमने एक अन्य रास्ते से अंदर प्रवेश किया तो देखा कि वहां पर अब भी गायें चर रही हैं। ये किसी रास्ते से आवाजाही कर रही है, यह तो ताला लगाने वाले ही बता सकते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह रही कि हमको आयड़ में कुछ ऐसे लोग भी मिल गए जो वहां पर मजे से बैठ कर एकांत में अपना गला तर करने के लिए आए हुए थे। इनके पास बोटलें साफ देखी जा सकती है। ये लोग कौनसा पेय पदार्थ पीने इतने अंदर तक चले आए, यह तो जांच का विषय है। सवाल ये है कि क्या अब ताला लगाने के बाद भी शीतल वाला पेय पदार्थ पी कर मानसिक तरेण महसूस करने व गम

गलत करने की चाहत रखने वालों के लिए आयड़ पहली पसंदीदा जगह बनी हुई है। इनकी रोक टोक कौन करेगा? ऐसा यहां रोज हो रहा है इसका सुबूत आस पास ही पड़ी शराब की बोटलों से आसानी से देखा जा सकता है। अब आयड़ में नियमित गश्त व धरपकड़ की सख्त जरूरत है। क्योंकि अगर तरल पदार्थ पीने वाले यूं ही बिना बुलाए दिन के उजाले में तशरीफ लाते रहेंगे तो जनता भूलकर भी आयड़ के विकास कार्यों का रूख करने वाली नहीं है। इसके साथ ही यहां पर ताला लगवाने वालों को एक बोर्ड भी लगाना चाहिए कि 85 करोड़ खर्च होने के बाद भी यहां पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जो भी आए अपनी रिस्क पर आवाजाही करे। आज हमें यहां नदी में गंदा, काला, बदबूदार झाग वाला गंदा पानी व कचरा भी दिखाई दिया। याने प्रदूषण में कोई कमी नहीं आइर है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने आयड़ को शायद कूड़ेदान समझ लिया है। अधिकारी भी शायद इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी बहता हुआ आए और गंदा पानी व कचरा बह कर आगे चला जाए और नदी को साफ करने की उनकी टेंशन और लायबिलिटी ही खत्म हो जाए। हमारा यह मानना है कि यदि शहरवासी जागरूक रहेंगे व अपने टेक्स के पैसों से किए जा रहे विकास के कामों का खुद अवलोकन करते रहेंगे तो पूरा सिस्टम चुस्त और दुरुस्त रहेगा। और अगर नेताओं व अफसरों के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया तो आमजन के लिए ताले लगे रहेंगे लेकिन आयड़ में शराब पीने वालों के सिलसिले यूं ही चलते रहेंगे।

उदयपुर में वकीलों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस से धक्का-मुक्की दो दिन में गिरफ्तारी नहीं होने पर फिर प्रदर्शन की चेतावनी



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। शुक्रवार को शहर में वकीलों ने कलेक्ट्रेट परिसर में उग्र प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों वकील रैली के रूप में कलेक्ट्री पहुंचे और पुलिस-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान 'एसपी हाय-हाय' के नारे भी लगे। वकीलों ने कलेक्ट्रेट भवन की पहली मंजिल पर स्थित एसपी ऑफिस तक जाने का प्रयास किया, लेकिन वहां तैनात पुलिस बल ने उन्हें सीढ़ियों पर ही रोकने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस और वकीलों के बीच धक्का-मुक्की हो

के साथ 3 से 4 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें एक महिला वकील के साथ मारपीट और एक वरिष्ठ वकील पर जानलेवा हमला शामिल है। उन्होंने कहा कि शहर में वकीलों पर हो रही घटनाओं को लेकर पुलिस से लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में शुक्रवार को कोर्ट में हड़ताल रखी गई और प्रशासन के समक्ष प्रदर्शन किया गया। शक्तावत ने चेतावनी दी कि अगर आगामी दो दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वकील समुदाय फिर से उग्र प्रदर्शन करेगा।

राजस्थान में बारिश ने तोड़े रिकॉर्ड: अब तक 128% ज्यादा बारिश, कई जिलों में अलर्ट



24 न्यूज अपडेट

जयपुर । राजस्थान में मानसून सक्रिय बना हुआ है और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह सवाई माधोपुर में सीजन की पहली अच्छी बारिश हुई, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं, टोंक जिले के बीसलपुर बांध में 24 घंटे के भीतर 42 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई है। राज्य में अब तक औसत से 128% अधिक बारिश हो चुकी है।

सवाई माधोपुर में एक घंटे की मुसलधार बारिश

शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे सवाई माधोपुर शहर में तेज बारिश शुरू हुई, जो 8 बजे तक चली। एक घंटे की बारिश ने पुराने शहर

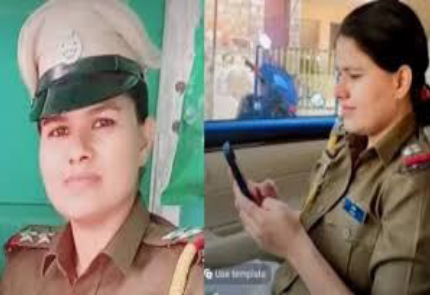
के कई इलाकों को पानी-पानी कर दिया। एसबीआई, बीओबी और एचडीएफसी बैंक के सामने की सड़कें जलमग्न हो गईं। वहीं कलेक्ट्रेट के पीछे ठिंगला इलाके में भी जलभराव की स्थिति बनी रही। हालांकि करीब 9 बजे बाद मौसम साफ हो गया और धूप खिल आई। मौसम विभाग के अनुसार, सवाई माधोपुर में पिछले 24 घंटे में 9.7 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई है और अगले दो दिन अच्छी बारिश की संभावना है।

बीसलपुर बांध के जलस्तर में हुआ इजाफा

टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार सुबह 6

बजे जलस्तर 313.49 मीटर तक पहुंच गया, जो कि इसके पूर्ण भराव स्तर से महज 2 मीटर नीचे है। बीते 24 घंटे में बांध में 42 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। वर्तमान में बांध में 24.789 टीएमसी (Thousand Million Cubic Feet) पानी संग्रहित है। त्रिवेणी क्षेत्र में 3.90 मीटर का प्रवाह दर्ज हुआ है, जबकि बांध क्षेत्र में 7 मिमी बारिश हुई। इस मानसून में अब तक बांध क्षेत्र में कुल 276 मिमी वर्षा हो चुकी है। राज्यभर में अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए जयपुर, दौसा और टोंक जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि श्रीगंगानगर को छोड़कर शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है। विभाग ने अगले 3-4 दिन तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। राजस्थान में इस बार मानसून ने जोरदार शुरुआत की है। अब तक राज्य में औसत से 128% अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिससे किसानों और आमजन दोनों में खुशी का माहौल है।

जयपुर पुलिस ने फर्जी महिला एसआई को किया गिरफ्तार: दो साल तक आरपीए में वर्दी पहनकर घूमती रही, वॉट्सऐप कॉल से धमकाती थी लोगों को



को प्रशिक्षु एसआई बताकर आईपीएस, आरपीएस और अन्य अफसरों के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालती थी। यही नहीं, वह पुलिस की कार्रवाई का धौंस

दिखाकर वॉट्सऐप कॉल के जरिये सीकर क्षेत्र के लोगों को धमकाती थी थी।

आरपीए में प्रवेश के लिए इस्तेमाल करती थी अफसरों वाले गेट

पुलिस जांच में सामने आया कि मोना बगैर किसी वैध पहचान के आरपीए में प्रवेश करती थी। वह मुख्य द्वार से जाने के बजाय उस गेट का इस्तेमाल करती थी, जो वरिष्ठ अधिकारियों व उनके परिजनों के लिए आरक्षित होता है। इससे वह आईडी चेकिंग से बच जाती थी। यही नहीं, ट्रेनिंग के दौरान उसने पुलिस से बचने के कई तरीके भी सीख लिए थे।

धमकी भरे वॉट्सऐप मैसेज से हुआ खुलासा

मोना एक एसआई के वॉट्सऐप ग्रुप में भी शामिल थी। एक बार उसने ग्रुप में मौजूद एक वास्तविक एसआई को धमकी दे दी। इससे शक होने पर उस एसआई ने इसकी शिकायत पुलिस अकादमी प्रशासन से की। जब जांच हुई, तो पता चला कि मोना का नाम किसी भी बैच में दर्ज नहीं है। इसके बाद

वर्ष 2023 में आरपीए की ओर से शास्त्री नगर थाने में मोना के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की एफआईआर दर्ज करवाई गई। किराए के मकान में कोचिंग छात्रा बनकर रह रही थी पुलिस की दबिश की खबर लगने के बाद मोना शास्त्री नगर स्थित किराए के मकान से फरार हो गई थी। तलाशी में उसके कमरे से पुलिस की वर्दी, बैच, फर्जी आईडी कार्ड और बेल्ट भी बरामद हुए थे। दो साल तक फरार रहने के दौरान वह सीकर में एक किराए के मकान में कोचिंग छात्रा बनकर रहने लगी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सीकर में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

अब फर्जीवाड़े के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मोना को आरपीए में एंट्री दिलवाने में किन लोगों ने मदद की, क्या किसी अंदरूनी व्यक्ति का सहयोग उसे मिला था, और उसने पुलिस की वर्दी और पहचान से जुड़ा सामान कहां से प्राप्त किया। पुलिस यह भी जांच रही है कि मोना ने फर्जी एसआई बनकर किन-किन लोगों से संपर्क किया और क्या उसने कोई वित्तीय या अन्य लाभ उठाया। प्रारंभिक धाराएं – IPC 420 (धोखाधड़ी), 468 (फर्जी दस्तावेज तैयार करना), 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग), और अन्य संबंधित धाराएं दर्ज की गई हैं।



24 न्यूज अपडेट

अहमदाबाद, 4 जुलाई अहमदाबाद से उड़ान भरते ही एअर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश में जान गंवाने वाले 270 लोगों के परिवार अब न्याय और मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रिटेन की कानूनी फर्म स्टीवर्ट्स ने आरोप लगाया है कि एअर इंडिया पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने से बचने की कोशिश कर रही है। फर्म के वकील पीटर नीन ने कहा है कि एयरलाइन ने मुआवजा देने से पहले पीड़ित परिवारों से अत्यधिक संवेदनशील वित्तीय विवरण मांगे, जिससे भविष्य में उन्हें कम मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि एअर इंडिया की यह रणनीति अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और करीब 1,050 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश

का हिस्सा हो सकती है। नीन ने आरोप लगाया कि एअर इंडिया के प्रतिनिधि मृतकों के परिजनों के घर जाकर फॉर्म भरने का दबाव बना रहे हैं। परिजनों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि जब तक वे फॉर्म नहीं भरते, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। जबकि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जैसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत, विमान हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को पहचान और दस्तावेज सत्यापन के बाद बिना शर्त अंतरिम मुआवजा देना जरूरी है। एअर इंडिया ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा कि फॉर्म का उद्देश्य केवल रिश्ते की पुष्टि करना है, ताकि मुआवजा सही व्यक्ति तक पहुंचे। एयरलाइन ने यह भी कहा कि कुछ परिवारों को अंतरिम भुगतान दिया जा चुका है और वे सभी प्रक्रियाएं पूरी

संवेदनशीलता से कर रहे हैं।

हादसा कैसे हुआ?

12 जून को दोपहर 1:38 बजे फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। मात्र दो मिनट बाद, 625 फीट की ऊंचाई पर विमान से मेडे कॉल (आपातकालीन संदेश) भेजा गया। इसके तुरंत बाद विमान कंट्रोल से बाहर हो गया और सिविल अस्पताल के पास एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत पर गिरकर क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग हॉस्टल की इमारत में मारे गए। कुल मिलाकर 270 लोगों की मौत हुई। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे।

डीएनए से पहचान, शवों का अंतिम संस्कार

अब तक 251 मृतकों की डीएनए से पहचान की जा चुकी है और 245 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। इस बीच विमानन नियामक DGCA ने 21 जून को एयर इंडिया के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण उनके पद से हटाने के आदेश दिए। इसमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग मैनेजर पिंकी मित्तल और

योजना अधिकारी पायल अरोड़ा शामिल हैं।

हादसे के आठ दिन बाद पार्टी, एयर इंडिया ने चार

कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा हादसे के सिर्फ आठ दिन बाद एअर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग यूनिट AISATS के चार कर्मचारियों का पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हो गया। एयरलाइन ने इसे असंवेदनशील करार देते हुए चारों से इस्तीफा मांग लिया। एअर इंडिया ने कहा – “इस दर्दनाक हादसे से प्रभावित परिवारों के प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। वायरल वीडियो में दिखाया गया व्यवहार हमारी नीति के खिलाफ है और हमने जिम्मेदारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।” जांच की मांग और कानूनी लड़ाई एडवोकेट पीटर नीन ने हादसे और उसके बाद एअर इंडिया की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को सलाह दी है कि वे एयरलाइन के फॉर्म न भरें और सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाएं। अब सवाल यह है कि क्या एअर इंडिया महज औपचारिकता निभाकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, या वास्तव में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में कोई ठोस प्रयास कर रही है?



उदयपुर में 17 वर्षों बाद होगा राष्ट्रसंत पुलकसागर महाराज का चातुर्मास, 6 जुलाई को शोभायात्रा के साथ होगा मंगल प्रवेश



24 न्यूज़ अपडेट

उदयपुर। झीलों की रमणीय धरती उदयपुर आगामी सप्ताह से आध्यात्मिक चेतना की उस गूंज से सराबोर होने जा रही है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नगरवासियों ने पिछले सत्रह वर्षों पूर्व किया था। वर्ष 2008 में जब राष्ट्रसंत जैनाचार्य पुलकसागर महाराज ने लेकसिटी को अपने चातुर्मास का सौभाग्य प्रदान किया था, तब यह नगर संयम, शांति और साधना के रंगों में रंग उठा था। एक लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2025 का यह वर्ष पुनः उसी शुभता को संजोने वाला सिद्ध हो रहा है, जब आचार्यश्री का चातुर्मास सकल जैन समाज के तत्वावधान में सर्वश्रेष्ठ विलास स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में संपन्न होगा। इस पावन अवसर का शुभारंभ 6 जुलाई, रविवार को प्रातः 7:30 बजे फतह स्कूल प्रांगण से एक भव्य शोभायात्रा के साथ होगा,

जिसमें नगर धर्म और संस्कृति के भव्यतम रंगों से सुसज्जित दिखाई देगा। शोभायात्रा में शामिल होंगे सजे-धजे हाथी, घोड़े, बगियां, विभिन्न वेशभूषाओं में सजे समाजबन्ध, ढोल-नगाड़ों और बैड की स्वरलहरियों पर झूमते श्रद्धालु। यह शोभायात्रा सूरजपोल चौराहे से गुजरते हुए नगर निगम परिसर, टाउन हॉल तक पहुंचेगी, जहां आचार्यश्री का मंगल प्रवचन होगा तथा तत्पश्चात विशाल स्वामीवात्सल्य का आयोजन भी किया जाएगा। चातुर्मास समिति के कार्याध्यक्ष आदिश खोड़निया ने बताया कि गुरुपूर्णिमा के शुभ अवसर पर 12 जुलाई को दोपहर 2 बजे टाउन हॉल में 'गुरु गुणगान महोत्सव' आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु विविध रूपों में गुरु भक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इसके एक दिन बाद, 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे वहीं दिव्य मंगल कलश की स्थापना की जाएगी, जिसमें श्रद्धालु

विशेष बोली लगाकर कलश स्थापना का सौभाग्य अर्जित करेंगे। चातुर्मास के आयोजनों की श्रृंखला में 27 जुलाई से 15 अगस्त तक 'ज्ञान गंगा महोत्सव' का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव के दौरान प्रतिदिन धर्म और ज्ञान की गंगा राष्ट्रसंत के विशेष प्रवचनों के रूप में प्रवाहित होगी। यह प्रवचन केवल जैन धर्म तक सीमित नहीं होंगे, अपितु सर्वधर्म समभाव को लेकर चलने वाले होंगे। इस दौरान 31 जुलाई को मोक्ष सप्तमी, 9 अगस्त को रक्षाबंधन तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसरों पर विशेष आयोजन प्रस्तावित हैं। इन आयोजनों में भाग लेने हेतु उदयपुर सहित डूंगरपुर, बांसवाड़ा, साबला, सागवाड़ा, धरियावद, कानोड़, अण्डीदा, भीण्डर आदि अंचलों से श्रद्धालु पहुंचेंगे। चातुर्मास के दूसरे चरण में 28 अगस्त से 6 सितंबर तक पर्वराज पर्युषण महापर्व की श्रृंखला आयोजित होगी। इस दौरान उपवास, साधना, स्वाध्याय, क्षमा, संयम और तप के अनेक आध्यात्मिक प्रयोग नगर को पवित्रता से भर देंगे। बड़ी संख्या में तपस्वी विविध तप करेंगे, जिनका महापराणा 7 सितंबर को होगा। इस सात दिवसीय तप साधना की पूर्णता के पश्चात 14 सितंबर को समूचा जैन समाज क्षमा याचना के साथ 'क्षमावाणी पर्व' मनाएगा। चातुर्मास समिति के मुख्य संयोजक

पारस सिंघवी, संयोजक अशोक शाह एवं गौरवाध्यक्ष शांतिलाल मनोत ने संयुक्त रूप से बताया कि यह चातुर्मास आयोजन केवल धार्मिक परंपरा नहीं, अपितु नगर की सांस्कृतिक चेतना को पुनः जागृत करने का एक यशस्वी अवसर है। इस आयोजन के माध्यम से नई पीढ़ी को संयम, सेवा, सत्य और साधना का मार्ग दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। महामंत्री प्रकाश सिंघवी के अनुसार पर्युषण पर्व के साथ ही कई सांस्कृतिक, साहित्यिक व नैतिक आयोजनों की रूपरेखा भी तय की जा चुकी है, जिन्हें समय-समय पर नगरवासियों को सूचित किया जाएगा। कोषाध्यक्ष श्रीपाल धर्मावत ने बताया कि वर्ष 2015 में भी हीरामन टावर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के दौरान आचार्यश्री का सात्रिध्न्य प्राप्त हुआ था, लेकिन चातुर्मास जैसा विस्तारपूर्ण आयोजन 2008 के बाद अब जाकर पुनः साकार हो रहा है। इस आयोजन में अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद फांदोत की प्रेरणा, विप्लव कुमार जैन के प्रचार-प्रसार संयोजन, और मेवाड़ जैन युवा संस्थान की 51 बुलेट रैली जैसी अभिनव पहल आयोजन को गौरवशाली बनाएगी। शोभायात्रा और प्रवचनों की श्रृंखला में युवाओं, महिलाओं, बच्चों और रिश्तेदारों की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

हर्षोल्लास के साथ मालदास स्ट्रीट में हुआ जैनाचार्य रत्नसेन सूरेश्वर महाराज का चातुर्मासिक प्रवेश



24 न्यूज़ अपडेट

उदयपुर, 4 जुलाई। श्री श्वेम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ-मालदास स्ट्रीट में शुक्रवार को जैनाचार्य श्रीमद् विजय रत्नसेन सूरेश्वर महाराज आदि ठाणा-5 एवं साध्वी समर्पणलीना श्रीजी महाराज आदि ठाणा-4 का चातुर्मासिक वर्षावास बड़े हर्षोल्लास के साथ इस प्रवेश हुआ। श्रीसंघ के कोषाध्यक्ष राजेश जावरिया ने बताया कि प्रातः 8.30 बजे सकल संघ के श्री पद्मनाथ स्वामी जैन मंदिर चौगान-शिक्षा सर्कल से गाजे-बाजे की रमझट के साथ, 1 हाथी, 4 घोड़े, श्री हीर सूरि जैन पाठशाला के बालक, बालिकाएँ, बगियों में सुशोभित पुज्य आचार्य रामचन्द्र सूरेश्वरजी महाराज एवं पूज्य भद्रंकर विजयजी की तस्वीरों, से युक्त सकल श्रीसंघ की प्रवेश यात्रा चेतक सर्कल एवं हाथीपोल के मार्ग से मालदास स्ट्रीट में संपन्न हुई। चातुर्मास प्रवेश के इस प्रसंग पर मुम्बई, पूना, चैन्नई, कोयम्बतूर, पोयनाड,

अमदाबाद, रोहा, पोसालिया, भायंदर, चिंचवड, थाणा, कर्जत, आदि विभिन्न शहरो से बड़ी संस्था में गुरुभक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। नूतन आराधना भवन-मालदास स्ट्रीट में धर्मसभा का आयोजन हुआ। संगीत सम्राट-अनीलजी गेमावत ने भक्ति संगीत के साथ जैनाचार्य श्री का प्रवेश करवाया। ज्ञानदीप प्रकट करने के बाद गुरु पूजन का चढ़ावा रतनबाई धनराज रांका परिवार-सादडी हाल-चिंचवड ने एवं कामली अर्पण का चढ़ावा भरत भाई कोठारी - बाली एवं भरतभाई छाजेड-सेवाडी वालों ने लिये। इस प्रसंग पर जैन हिन्दी साहित्य दिवाकर पूज्य आचार्य रत्नसेनसूरेश्वर महाराज द्वारा अलिखित 255वीं हिन्दी पुस्तक 10 श्रमण धर्म का भव्य विमोचन पधारे हुए गणमान्य लोगों के द्वारा किया गया। श्री महावीर साधना केन्द्र-अम्बामाता स्कीम के महासचिव फतेह सिंह मेहता आदि ने आचार्यश्री को पुनः

आगामी वर्ष 2026 के चातुर्मास की विनती की। धर्मसभा में प्रवचन देते हुए जैनाचार्य रत्नसेन सूरेश्वर ने कहा कि जनजीवन की जीवनशैली को बदलने के लिए विज्ञान ने कई सुख सुविधा के साधन दिये। पहले व्यक्ति पैदल चलते थे आज हवा में उड़ते हैं, पहले सभी काम हाथों से होता था, आज विद्युतीय साधनों से होते हैं। परंतु विज्ञान के साधनों ने सुख सुविधाओं के साथ मौत का खतरा भी दिया है। समय बचाने के साधन दिये तो समय भक्षी साधनों को देकर जनजीवन को धर्म स्थान, धर्मक्रियाएँ और धार्मिक ज्ञान से दूर कर दिया है। विज्ञान के साधन आत्मिक पतन कराने वाले हैं, जबकि धर्म की साधना आत्मिक उद्धार कराने वाली है। चारित्र्य जीवन के 49 वे वर्ष में हजारों किलोमीटर पैदल विचरण के बाद आज 34 वर्ष के बाद इसी उदयपुर के प्रांगण में पुनः चातुर्मास का आयोजन हुआ है। चातुर्मास के अवसर पर हमारे जीवन में साधनों की दीड़ छोड़कर आत्मिक साधना में जुड़ने का प्रयत्न करना है। कार्यक्रम के बाद सामूहिक प्रभावना हुई। 6 जुलाई को प्रातः 9.30 बजे गौतम स्वामी वंदना-संवेदना का संगीत मय कार्यक्रम होगा। अध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र हिरण, मंत्री कुलदीप नाहर, कोषाध्यक्ष राजेश जावरिया, फतेहसिंह मेहता, जसवंत सिंह सुराणा, रakesh चेलावत, अभिषेक हिम्मत, हरिश सिंघवी आदि उपस्थित रहे।

शांतिनाथ भगवान का महाभिषेक व नंदीश्वर विधान सम्पन्न



पर आयोजित आठ दिवसीय नन्दीश्वर द्वीप म ह । म ण ड ल विधान के तहत विधान किया गया। विधान प्रातः प्रतिष्ठा चार्य

भगवान की प्रतिमाओ को पाण्डूक शिला पर स्थापित कर पंचामृत अभिषेक किया गया साथ ही यजमान परिवार द्वारा प्रतिष्ठाचार्य पगारिया के मंत्रोच्चारण के साथ विश्व शांति कामनार्थ मूलनायक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा पर शांतिधारा की गयी। इसके बाद महिला मंडल द्वारा देव शास्त्र गुरु पूजा, आदिनाथ पूजा के बाद नन्दीश्वर विधान पूजा के तहत अष्ट द्रव्य श्रीफल युक्त विधान मण्डल पर अर्घ समर्पित किये गये अन्त मे आरती उतारी गयी।

24 न्यूज़ अपडेट

24 न्यूज अपडेट, सागवाड़ा (जयदीप जोशी)। नगर के श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन गांधियों का मंदिर मे शुक्रवार कोआषाढी अष्टान्हिका महापर्व के अवसर

24 न्यूज़ अपडेट

24 न्यूज अपडेट, सागवाड़ा (जयदीप जोशी)। क्षेत्र भर में विगत कुछ दिनों से हो रही लगातार बरसात से नगर सहित आस-पास ग्रामीण क्षेत्र में तालाबों में पानी की आवक तेज होकर भरने के कंगार में वही खेतों में भरे पानी से कृषकों में मायूसी छा गई। गत कुछ वर्षों के बाद इस वर्ष मानसून जून माह में आ जाने से लोगों में खुशी का माहौल छा गया विगत कई वर्षों से मानसून जुलाई माह के मध्य या अन्त में आता है इस वर्ष जून माह में ही आ गया। विगत कुछ दिनों

से नगर सहित आस-पास ग्रामीण क्षेत्र कभी रात को तो कभी दिन में कभी दिन रात बरसात होने से नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र में तालाबों में पानी की अच्छी आवक से तालाब भरने के कंगार में वही नगर का मसानिया तालाब व गमलेश्वर तालाब भी भर गया है पानी छलकने कि स्थिती है। वही लगातार हो रही बरसात के चलते खेतों में पानी भर गया है जिससे किसानों को बुवाई में परेशान का सामना करना पड रहा है वही कुछ किसानों ने तो बुवाई भी कर दि है जिससे हो रही बरसात से फसल खेतों में नष्ट होने का भव्य

बना हुआ है यदी बरसात रूक जाती है तो इस वर्ष अच्छी फसल होने की सम्भावना बनी हुई है। चावल की फसल के लिए खेत पुरी तरह से भर गये है। शुक्रवार को दिन में मौसम ने खुला निकाला लेकिन 2:30 पर आकाश में बादल छाये तथा रिमझीम बरसात प्रारम्भ हुई उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद बरसात तेज प्रारम्भ हुई जो समाचार लिखने तक चल रही थी। सागवाडा रैनजेंज स्टेशन के अनुसार 4 जुलाई प्रातः 24 घण्टे तक 12 एमएम बरसात हुई साथ ही अभी तक कुल 607 एमएम बरसात मापी गई।

आर्द्रभूमि संरक्षण पर क्षेत्रीय सहभागिता कार्यशाला संपन्न, मेनार वेटलैंड संरक्षण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर



24 न्यूज़ अपडेट

उदयपुर. आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं उनके समझदारीपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु एक क्षेत्रीय सहभागिता कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को उदयपुर में किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सहयोगी संस्थाओं के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में मध्य और पश्चिमी भारत के राज्यों — राजस्थान, मध्य प्रदेश,

गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ — के राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों, पर्यावरण विशेषज्ञों और स्थानीय समुदाय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान वेटलैंड सिटी मान्यता, सहभागितापूर्ण संरक्षण रणनीतियां और SAC द्वारा प्रकाशित आर्द्रभूमि एटलस 2021 के संदर्भ में राज्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। विभिन्न सत्रों में रामसर साइट्स के नामांकन की प्रक्रिया, आर्द्रभूमियों के स्वास्थ्य मूल्यांकन और प्रबंधन

में समुदायों की भूमिका को केंद्र में रखा गया। कार्यक्रम का समापन मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। यह एमओयू क्षेत्रीय सहयोग, स्थायी संरक्षण प्रयासों और जैवविविधता संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अंधा कानून, अंधा तंत्र!! जानलेवा हमला करने वाले ने किया समझौते के लिए मजबूर, छूटते ही कर दी शिक्षिका की बेरहमी से हत्या, दोषी कौन?



24 न्यूज़ अपडेट

24 न्यूज अपडेट, बांसवाड़ा। क्या हम अंधे कानून वाले अंधे तंत्र में जी रहे हैं। महिला पर जानलेवा हमला होता है, वह गुजरात में भर्ती रहती है। कई महीनों तक गायब रहने के बाद अपराधी पकड़ा जाता है। फिर उसका भाई महिला पर दबाव बनाकर समझौता करवा देता है। उससे लिखवा देता है कि अब उसे आरोपी से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद कानून भी अपराधी को आजाद कर देता है। बिना इस खतरे ही आहत भांपे कि बाहर आकर यही व्यक्ति उसी महिला का तलवार से बेरहमी से कल्ल कर देगा। बांसवाड़ा जिले में एक सरकारी शिक्षिका की दिनदहाड़े सड़क पर तलवार से हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। 36 वर्षीय लीला ताबियार की जान उस व्यक्ति ने ली, जिसे कभी उसने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। यह हत्या महज एक व्यक्तिगत रंजिश या संबंध-विच्छेद का मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक दबाव, न्याय तंत्र की असफलता और डर के साये में किए गए समझौतों की परिणति है। 1 जुलाई को सुबह करीब 10:30 बजे, बांसवाड़ा के कलिंजरा बस स्टैंड पर लीला रोज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार थी। सज्जनगढ़ ब्लॉक

के छाया महुड़ी स्थित सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाने वाली लीला, अपने ही गांव अरथूना के तरीयापाड़ा से बस पकड़ने आई थी। तभी नीले रंग की अल्टो कार से उसका पूर्व प्रेमी महिपाल भगोरा वहां पहुंचा। उसने लीला से कहा कि वह उसे स्कूल छोड़ देगा। पहले तो लीला झिझकी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। कार में बैठते ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। लीला ने गाड़ी रुकवाई और बस स्टैंड की एक दुकान के बाहर बैठकर बस का इंतजार करने लगी। महिपाल वहां से चला गया। लेकिन कुछ ही देर में वह वापस लौटाकूइस बार हाथ में तलवार लेकर। जैसे ही लीला ने उसे देखा, वह संभल पाती इससे पहले ही महिपाल ने उस पर हमला कर दिया। सड़क पर दौड़ते हुए वह लीला की ओर लपका और एक के बाद एक कई वार किए। भीड़ कुछ समझ पाती, उससे पहले लीला लहलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फरार होने की कोशिश में महिपाल की कार एक पेड़ से टकरा गई, लेकिन वह गाड़ी छोड़कर भाग निकला। अभी तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। इस निर्मम हत्या से पहले भी लीला पर जानलेवा हमला हो चुका था। अगस्त 2023 में भी महिपाल ने तलवार से लीला के गले और हाथ पर ताबड़तोड़ वार किए थे, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुई थी। महीनों तक इलाज चला। मामला पुलिस तक पहुंचा, महिपाल जेल गया, लेकिन सजा पूरी करने से पहले ही लीला पर फिर दबाव बनने लगा। महिपाल के भाई चेतन महिपाल ने डेढ़ महीने पहले उसके घर जाकर धमकी दी कि अगर महिपाल को जेल से नहीं छुड़ाया तो वह बाहर आकर लीला को जान से मार देगा। इस धमकी ने वह काम किया जो कोर्ट के आदेश नहीं कर सके। डर, सामाजिक दबाव और बदनामी के भय ने लीला को झुकने पर मजबूर कर दिया। उसने केस वापस ले लिया, अदालत में बयान दिया कि अब

उसे महिपाल से कोई खतरा नहीं है। नतीजा यह हुआ कि आरोपी जेल से छूट गया और जैसे ही छूटा, वही डर हकीकत बन गया। मृतका के भाई श्रवण ताबियार ने बताया कि लीला संविदा पर गड़ी उपखंड के सरेड़ी बड़ी गांव के कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत थी, यहीं उसकी महिपाल भगोरा से मुलाकात हुई थी। दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे और लिंव-इन में रहने लगे। लीला तलाकशुदा थी और महिपाल उस पर अधिकार जताने लगा था। जब 2023 में लीला को सरकारी नौकरी मिली और उसने दूरी बनानी शुरू की, तो महिपाल ब्लैकमेल करने लगापैसों के लिए, भावनात्मक दबाव डालकर। दूरी बढ़ी तो महिपाल ने हिंसा का रास्ता अपना लिया। इस हत्या से ठीक पहले महिपाल ने दो वीडियो भी शूट किए, जिनमें उसने खुद को ठगा हुआ बताया। वीडियो में वह कहता है कि लीला ने उसे पढ़ाया, आगे बढ़ाया और फिर छोड़ दिया। कार की अगली सीट पर उसकी मां बैठी थी, जो रोती रही, बेटे को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन महिपाल की आंखों में सिर्फ खून उतर आया था। लीला की हत्या सिर्फ उसके जीवन की समाप्ति नहीं, बल्कि एक सिस्टम की असफलता है। वह सिस्टम जो पीड़िता से ही यह साबित करवाने की मांग करता है कि खतरा खत्म हो गया है। वह समाज जो महिला से यह अपेक्षा करता है कि वह समझौता करे, भले ही उसकी कीमत उसकी जान क्यों न हो। आज महिपाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पहली बार के हमले को गंभीरता से लिया गया होता, अगर धमकी को कानूनी सुरक्षा मिली होती, अगर लीला को समझौता करने पर मजबूर नहीं किया गया होता तो क्या वह आज जिंदा होती? इस सवाल का जवाब अब न पुलिस के पास है, न अदालत के पास। यह जवाब समाज को खुद से मांगना होगा।

जिला परिषद की साधारण सभा में गरमाए जनहित के मुद्दे, फर्जी पट्टों पर तीखी बहस



24 न्यूज़ अपडेट

जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख ममता कुंवर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी. जोशी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मोणा, मावली विधायक पुष्करलाल

डांगी, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, जिला कलेक्टर निमित मेहता, जिला परिषद सीईओ रिया डाबी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर गंभीर मंथन हुआ, जिसमें सबसे पहले चिकित्सा विभाग की स्थिति पर चिंता जताई गई। सदस्यों ने कहा कि रात्रिकालीन चिकित्सकों की अनुपलब्धता से ग्रामीण जनता को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। विशेषकर भीडर सीएचसी में शिशु रोग विशेषज्ञ के दो माह पूर्व हुए तबादले के बाद भी अब तक नया चिकित्सक नियुक्त नहीं हुआ, जिससे बच्चों के इलाज में परेशानी

हो रही है। सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। जिला परिषद सदस्य खयालीलाल सुहालका ने आरोप लगाया कि निर्माण में डामर की गुणवत्ता घटिया है और सैंपल लेकर जांच की जानी चाहिए। वहीं गिर्वा पंचायत समिति क्षेत्र में फर्जी पट्टों के वितरण का मामला गरमा गया। सदस्यों ने आरोप लगाए कि कागजातों में हेरफेर कर अवैध रूप से कई पट्टे जारी किए गए, जिसमें उपप्रधान मीना कुंवर की भूमिका संदिग्ध बताई गई और मामले की एसीबी से जांच कराने की मांग की गई। सीईओ रिया डाबी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पारदर्शिता सुनिश्चित करें और सभी लंबित व संदेहास्पद मामलों में शीघ्र कार्रवाई करें।